

सीआईएसएफ में महिला जवानों की संख्या बढ़ाई जाए : गृहमंत्री

शाह बोले, सिर्फ 6.38 फीसदी महिलाएं, 20% हो संख्या



गाजियाबाद में सीआईएसएफ के समारोह में परेड की सलामी लेते गृहमंत्री अमित शाह।

अमर उजाला ब्यूरो

गाजियाबाद। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में महिला जवानों की संख्या बढ़नी चाहिए। अभी इसमें कुल 9200 महिलाएं हैं, जो कुल फोर्स की मात्र 6.38 फीसदी है। इसे बढ़ाकर 20 फीसदी किया जाना चाहिए। उन्होंने आतंकवाद से लेकर नक्सलवाद तक से निपटने में सीआईएसएफ की भूमिका की तारीफ की। साथ ही यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन गंगा में योगदान को भी सराहा।

सीआईएसएफ के 10 मार्च को होने वाले 53वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में रविवार को इंदिरापुरम स्थित पांचवीं बटालियन में आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शाह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर से लेकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सीआईएसएफ के जवान डटे हुए हैं। 52 वर्षों के सफर में सीआईएसएफ ने सुरक्षा और शांति कायम करने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। ढाई बिलियन अर्थतंत्र की विकास यात्रा में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का कर्मयोगी की तरह योगदान रहा है।

ऑपरेशन गंगा में अहम भूमिका

यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चल रहा है, उसमें भी सीआईएसएफ का योगदान सराहनीय है। वर्ष 1970 में स्थापित सीआईएसएफ बल जो तीन हजार सदस्यों के साथ शुरू हुआ था, वो एक लाख 64 हजार जवानों का परिवार बन गया है।

■ उन्होंने कहा कि 22 वर्षों में सीआईएसएफ ने देश के संवेदनशील एयरपोर्ट, बंदरगाह, कोयला उत्पादन और अन्य क्षेत्रों में भूमिका निभाई। अब मेट्रो में रोजाना 30 लाख लोगों की सुरक्षा करके हमें गौरवान्वित करते हैं। हमें अब इससे आगे के बारे में सोचना पड़ेगा क्योंकि सीआईएसएफ का दायरा अब बढ़ने जा रहा है।

■ गृहमंत्री ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के विशिष्ट बल के रूप में सीआईएसएफ को रेखांकित किया है। 100वें वर्ष में आजादी की शताब्दी पर संकल्प महोत्सव मनेगा, तब तक सीआईएसएफ को और ऊंचाई पर ले जाने का लक्ष्य अभी से बना लेना चाहिए।

निजी सुरक्षा एजेंसियों को प्रशिक्षित करें

■ शाह ने कहा, जब देश का आर्थिक तंत्र ढाई बिलियन से बढ़कर पांच बिलियन होगा तो निजी औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षा का जिम्मा भी बढ़ जाएगा। ऐसे में सीआईएसएफ को पांच साल की बेस और 25 वर्ष की दीर्घकालीन योजना में निजी सुरक्षा एजेंसियों को प्रशिक्षित करने की तैयारी करनी होगी।